

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 17 फरवरी, 2016

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:-443/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-गंगोत्री में वरुणाघाटी में भराणागांव-ऊपरीकोट मोटर मार्ग के किमी0-5 में 30 मी0 स्पान के 1.50 लेन स्टील गर्डर सेतु को निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में उक्त सेतु के निर्माण की स्वीकृति अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत शासनादेश संख्या- 2580/111-2/06-44(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 19-10-2006 द्वारा ₹ 82.60 लाख की प्रदान की गई है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस सेतु का निर्माण वित्तीय वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत स्वीकृत ज्ञानसू-साल्ड-ऊपरीकोट मोटर मार्ग के किमी0-5 में किया जाना प्रस्तावित है। इस मोटर मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति माह अक्टूबर 2010 में प्राप्त होने तथा उक्त मोटर मार्ग निर्माणाधीन होने के दृष्टिगत इस सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। चूंकि वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग में पहाड़ कटान का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है तथा पार्ट-11 का कार्य प्रगति पर है। भविष्य में इस मोटर मार्ग का विस्तार स्यानाचट्टी (यमुनोत्री) तक प्रस्तावित होने के दृष्टिगत इस सेतु को निर्माण 1.50 लेन में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस मध्य सामग्री एवं श्रमिकों की दरों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होने एवं सेतु का निर्माण एक लेन के स्थान पर 1.50 लेन में किये जाने के कारण इस सेतु का निर्माण पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 82.60 लाख में सम्भव न हो पाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, टिहरी द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी सम्पूर्ण लागत ₹ 205.30 लाख है, पर विभागीय तकनीकी परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई पुनरीक्षित लागत ₹ 204.60 लाख (₹ 82.60 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 122.00 लाख अतिरिक्त लागत) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की, माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश सं0:- 2580/111-2/06-44(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 19-10-2006 के क्रमांक-33 पर अंकित उक्त कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 82.60 लाख को, वर्तमान में प्रस्तुत पुनरीक्षित विस्तृत आगणन पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 122.00 लाख में सम्मिलित करते हुए, विषयगत कार्य की कुल पुनरीक्षित लागत ₹ 204.60 लाख में उक्त सेतु का निर्माण पूर्ण कराया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को पूर्व स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19-10-2006 को केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

3- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

5- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

7- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

8- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

9- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- उक्त योजना पर होने वाला व्यय, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-30 लेखापीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-800 अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-01 चालू निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य की मद से, आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पत्रावलियों में दिये गये परामर्शानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- 655 (1)/111(2)/16-44(प्रा०आ०)/2006 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग टिहरी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/उत्तरकाशी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव